मनमानी | एसईसीएल के शारदा उप क्षेत्र में पदस्थ टेक्निकल इंस्पेक्टर दिलीप पांडे एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में

नजराना दो, तभी चलेगी गाड़ी !

प्रदीप शर्मा

नव भारत, धनपुरी/सोहागपुर एरिया। एसईसीएल के शारदा उप क्षेत्र में पदस्थ टेक्निकल इंस्पेक्टर दिलीप पांडे एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। कोयला परिवहन से जुड़े कई ट्रांसपोर्टरों, कर्मचारियों और सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर जो जानकारी साझा की है, उसने पूरे कोयला परिवहन तंत्र की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि शारदा उप क्षेत्र में कोयला परिवहन और गुणवत्ता प्रबंधन पूरी तरह 'नजराना संस्कृति' के तहत संचालित किया जा रहा है, जहां बिना कथित सुविधा शुल्क दिए न तो गाड़ियां आसानी से निकलती हैं और न ही गुणवत्तापूर्ण कोयला उपलब्ध होता है।

सूत्रों के अनुसार रोड सेल में कोयला लोड कराने वाले ट्रांसपोर्टरों को आए दिन तकनीकी कमियों और औपचारिक नियमों का हवाला देकर परेशान किया जाता है। यदि कोई ट्रांसपोर्टर 'साहब' की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, तो उसकी गाड़ियों को कभी गुणवत्ता जांच, कभी दस्तावेजों की त्रुटि तो कभी तकनीकी आपत्ति बताकर घंटों खड़ा रखा जाता है। इससे ट्रांसपोर्टरों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जिन ट्रांसपोर्टरों द्वारा कथित रूप से मोटी रकम पहुंचाई जाती है, उनकी गाड़ियां बिना किसी रुकावट के तेज़ी से निकल जाती हैं।

सबसे गंभीर आरोप कोयले की गुणवत्ता को लेकर लगाए जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि जिस उच्च गुणवत्ता वाले ल5 कोयले को नियमानुसार सुरक्षित स्टॉक में रखा जाना चाहिए, उसे कथित रूप से चुनिंदा ट्रांसपोर्टरों को रोड सेल में भेज दिया जाता है। जबकि सामान्य उपभोक्ताओं और अन्य कंपनियों को निम्न गुणवत्ता का कोयला उपलब्ध कराया जाता है। इससे उपभोक्ताओं को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है और एसईसीएल जैसी सार्वजनिक कंपनी की साख पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्षेत्र में चर्चा है कि टेक्निकल इंस्पेक्टर दिलीप पांडे पर यह पहला आरोप नहीं है। इससे पहले खैरा माइंस में भी उन पर भ्रष्टाचार, पक्षपात और अवैध लेनदेन के गंभीर आरोप लग चुके हैं। बताया जाता है कि लगातार शिकायतों के बाद उन्हें वहां से हटाकर शारदा ओपन कास्ट माइंस भेजा गया था। हालांकि कुछ समय तक स्थिति सामान्य दिखाई दी, लेकिन अब फिर वही पुराना खेल शुरू होने की चर्चाएं क्षेत्र में जोरों पर हैं। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि पूरा सिस्टम भय, दबाव और कथित वसूली की राजनीति पर चलाया जा रहा है। जो व्यक्ति या कंपनी 'विशेष सेवा शुल्क' देने को तैयार रहती है, उसे बेहतर गुणवत्ता का कोयला, तेज लोडिंग और प्रशासनिक सहयोग सब कुछ आसानी से मिल जाता है। जबकि नियमों के अनुसार काम करने वाले ट्रांसपोर्टरों को जानबूझकर प्रताड़ित किया जाता है, ताकि वे भी दबाव में आकर अवैध भुगतान करने को मजबूर हो जाएं। मामला यहीं तक सीमित नहीं है। सूत्रों के मुताबिक शारदा उप क्षेत्र में पदस्थ नोडल अधिकारी और ब्लास्टिंग अधिकारी पर भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि टेक्निकल इंस्पेक्टर दिलीप पांडे द्वारा बार-बार यह सवाल उठाया जाता है कि 'ल5 कोयले का डंप आखिर गया कहां?' जबकि क्षेत्र के कर्मचारियों का कहना है कि कोयले के परिवहन और डंपिंग से जुड़े अधिकांश निर्देश स्वयं टेक्निकल इंस्पेक्टर के स्तर से जारी किए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि कोयले के स्टॉक और परिवहन में गड़बड़ी हुई है तो उसकी जवाबदेही तय करने के बजाय अधीनस्थ अधिकारियों पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है?

सूत्रों का यह भी दावा है कि कई बार नोडल और ब्लास्टिंग विभाग के अधिकारियों को अनावश्यक रूप से निशाना बनाकर पूरे मामले की जिम्मेदारी उन पर डालने की कोशिश की जाती है, ताकि वास्तविक अनियमितताओं से ध्यान हटाया जा सके। इससे विभागीय कर्मचारियों में भी असंतोष का माहौल बना हुआ है।

क्षेत्र में यह चर्चा भी आम हो चुकी है कि एक तकनीकी निरीक्षक की सीमित सरकारी आय के बावजूद आलीशान जीवनशैली, महंगे संसाधन और प्रभावशाली नेटवर्क आखिर किन स्रोतों से खड़े हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि किसी स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कोयला परिवहन, गुणवत्ता प्रबंधन और अवैध लेनदेन से जुड़े कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोपों और लगातार उठ रही शिकायतों के बावजूद एसईसीएल प्रबंधन अब तक मौन क्यों है? क्या विभागीय अधिकारियों को इन गतिविधियों की जानकारी नहीं है, या फिर सब कुछ जानकर भी आंखें मूंद ली गई हैं? यदि समय रहते इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच नहीं कराई गई, तो इससे न केवल कंपनी को प्रतिदिन लाखों रुपये का नुकसान होता रहेगा, बल्कि एसईसीएल की विश्वसनीयता भी लगातार कमजोर होती जाएगी। कोयला परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अब आवश्यक हो गया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि आखिर शारदा उप क्षेत्र में 'सिस्टम' चला कौन रहा है नियम या फिर कथित नजराना तंत्र।

मौत के मुहाने पर मजदूर, जिम्मेदार मौन!

- इंडोर स्टेडियम निर्माण में सुरक्षा नियमों की खुलेआम धज्जियां, बिना सेफ्टी उपकरण ऊंचाई पर कराया जा रहा काम

नवभारत धनपुरी। नगर पालिका धनपुरी अंतर्गत निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम इन दिनों विकास से ज्यादा अव्यवस्था, लापरवाही और कथित अनियमितताओं को लेकर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। करोड़ों रुपये की लागत से बन रहे इस बहुमंजिला निर्माण कार्य में मजदूरों की जिंदगी को खुलेआम दांव पर लगाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। निर्माण स्थल पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे किसी बड़े हादसे की आशंका को साफ तौर पर दर्शाती हैं।

बताया जा रहा है कि उक्त निर्माण कार्य का ठेका इंदौर निवासी शिव राठौर की कंपनी को दिया गया है। आरोप है कि ठेकेदार द्वारा मजदूरों से बिना किसी सुरक्षा उपकरण के खतरनाक ऊंचाइयों पर काम कराया जा रहा है। न मजदूरों के सिर पर हेलमेट, न सुरक्षा बेल्ट, न जाल और न ही अन्य जरूरी सुरक्षा इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर नगर पालिका और निर्माण एजेंसी किस बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदेश और देश में निर्माण कार्यों के दौरान कई मजदूर ऊंचाई से गिरकर अपनी जान गंवा चुके हैं, बावजूद इसके धनपुरी के इंडोर स्टेडियम निर्माण में सुरक्षा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मजदूरों की मजबूरी और गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें जान जोखिम में डालने पर मजबूर किया जा रहा है। कुछ पैसों के लालच में मजदूर मौत के मुहाने पर चढ़कर काम करने को विवश हैं। सबसे बड़ा सवाल नगर पालिका की मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री पूजा बुनकर की कार्यप्रणाली पर खड़ा हो रहा है। आरोप लग रहे हैं कि अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए नियम-कायदों को ताक पर रखा जा रहा है। यदि निर्माण कार्य के दौरान कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या केवल ठेकेदार पर कार्रवाई कर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बच निकलेगा, या फिर उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की। हैरानी की बात यह है कि जिन अधिकारियों और इंजीनियरों को निर्माण कार्य की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे भी पूरी तरह उदासीन नजर आ रहे हैं। निर्माण स्थल पर मजदूरों की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की गंभीरता दिखाई नहीं दे रही। इससे साफ प्रतीत होता है कि नियम केवल कागजों तक सीमित हैं और जमीनी स्तर पर मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं बची है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कोई ठोस कार्रवाई करता है या फिर किसी बड़े हादसे के बाद केवल जांच और बयानबाजी तक ही पूरा मामला सीमित रह जाएगा।

भीषण सड़क हादसे में तीन की मौत

- कार और बाइक की जोरदार टक्कर में दो युवक व एक युवती ने गंवाई जान

नवभारत, शहडोल। जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मानपुर मार्ग पर स्थित बेडरा गांव के पास शनिवार दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा कार और बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर के कारण हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना इतनी भयावह थी कि बाइक सवार दो युवक और एक युवती गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर दूर जा गिरे। तीनों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। वहीं कार सवार एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक तीनों युवक-युवती बाइक से किसी काम से जा रहे थे। इसी दौरान बेडरा गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के ग्रामीण मदद के लिए दौड़ पड़े।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।

कलश यात्रा निकाल जल संरक्षण का दिया संदेश

नवभारत,शहडोल। नगर पालिका परिषद शहडोल द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बाणगंगा मंदिर परिसर से भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को जल संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जागरूक करते हुए जल बचाने का संदेश देना रहा। कलश यात्रा में महिलाओं, जनप्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों की दीदियों एवं नगर पालिका कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा के दौरान नगरवासियों को जल स्रोतों के संरक्षण एवं जल के समुचित उपयोग के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम स्थल पर आकर्षक रंगोलियां बनाकर जल है तो कल है जैसे प्रेरणादायी संदेशों के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण का महत्व बताया गया। इस दौरान वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण तथा दैनिक जीवन में जल की बचत को लेकर भी लोगों को प्रेरित किया गया।

पटवारी की मनमानी से तंग किसानों ने एसडीएम से की शिकायत

नवभारत,ब्योहारी। तहसील ब्योहारी के ग्राम देवरी मे पदस्थ ज्योति संत पटवारी की मनमानी से किसानो मे काफी आक्रोश है। उन्होंने बताया कि पटवारी साहिबा की मनमानी इस कदर हावी है कि वो अपने अधिकारी की भी नहीं सुनती। तहसीलदार द्वारा कई बार नोटिस जारी किया किन्तु वो उसे रद्दी की टोकरी मे फेक जबाब तक देना उचित नहीं समझती इनके मनमानी के आगे तहसीलदार भी बेबस और लाचार है तो भला हम किसानो का क्या हाल है उसका अंदाजा नही लगया जा सकता है।किसानो ने एसडीएम ब्योहारी को पत्र देकर पटवारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।

हल्का में पटवारी के न रहने से परेशान हो रहे किसान

पटवारी से तंग किसानो ने बताया कि ज्योति संत पटवारी नियमित रूप से हल्का मे नहीं रहती है। किसानो एवं आमजन को भूमि संबंधी कार्यों के लिये काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। खसरा खतौनी,नामांतरण, नक्सा फसल बीमा ऋण आदि कार्यों के लिए दस्तावेज हेतु परेशान होना पड़ता है। तहसीलदार और एसडीएम को कई बार शिकायत की गयी किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

पटवारी की मनमानी के आगे बेबस और लाचार तहसीलदार

किसानो ने बताया कि पटवारी हल्का मे नहीं रहती है महिने मे एकाद बार आती है। काम के नाम पर कास्तकारों से पैसा लिया जाता है इसके बाद भी उनका काम समय मे नही किया जाता। कई बार तहसीलदार शनि द्विवेदी से शिकायत की गयी उनके द्वारा नोटिस जारी किया गया इतना ही नही कार्यवाही के लिये अनुशंसा कर एसडीएम साहब को पत्र भी भेजा गया पर आज तक कोई कार्यवाही नही हुई। तहसीलदार का कहना है कि हम मजबूर है पटवारी के खिलाफ एसडीएम को कार्यवाही करने का अधिकार है।

घूंस की रकम वापस कराने की मांग

ग्राम पंचायत देवरी सरपंच नत्थूलाल सिंह ने किसान निरपत सिंह, लोकनाथ सिंह,रामसरोज सिंह और राजकरण सिंह से पटवारी पर पैसा लेने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पैसा लेने के बाद भी काम नहीं किया जा रहा। एसडीएम ब्योहारी को पत्र देकर पटवारी के खिलाफ कार्यवाही किये जाने और किसानो का पैसा वापस कराने की मांग की है।

इनका कहना है

कुछ किसानो द्वारा कल शिकायत की गयी है। सोमवार या मंगलवार तक पटवारी को वंहा से हटाने के लिये आदेश जारी कर दिया जायेगा।

भगीरथ लहरे
एसडीएम ब्योहारी

हल्की हवा का झोंका आया . . .

- और नवागांव फीडर ने ले लिया 24 घंटे का मौन व्रत!

नवभारत, गोहपारू। खन्नौधी वितरण केंद्र अंतर्गत आने वाला नवागांव फीडर इन दिनों अपनी 'अद्भुत संवेदनशीलता' के कारण पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि जैसे ही मौसम ने हल्की सी अंगड़ाई ली और हवा ने दो-चार झोंके मार दिए, वैसे ही बिजली व्यवस्था भावुक होकर धराशायी हो गई और पिछले 24 घंटे से अधिक समय से क्षेत्र अंधेरे में डूबा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली इतनी नाजुक निकली कि लगता है फीडर लोहे-तार से नहीं बल्कि भावनाओं से बनाया गया था। हल्की हवा चली नहीं कि पूरा सिस्टम 'मैं नहीं कर पाऊँगा' बोलकर बैठ गया। इधर जनता रातभर मच्छरों के साथ लोकतांत्रिक बैठक करती रही, बच्चे गर्मी में तड़पते रहे, बुजुर्ग हाथ वाले पंखे से खुद को सांत्वना देते रहे, पानी की मोटरें बंद पड़ी रहीं और मोबाइल फोन ऐसे पड़े रहे जैसे किसी संग्रहालय में रखी पुरानी वस्तुएँ हों। लेकिन बिजली विभाग की कार्यशैली देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरा विभाग किसी गहरे ध्यान और साधना में लीन हो। जब परेशान ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया तो जवाब भी किसी ऐतिहासिक घोषणा से कम नहीं था।

अभी ऐसे ही होगा जब तक सुधार कार्य होगा तब तक बिजली चालू नहीं हो सकती। यानि जनता समझ ले कि बिजली कोई सुविधा नहीं, बल्कि भगवान के दर्शन की तरह है — कब मिल जाए, कोई भरोसा नहीं।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि बिजली विभाग ने शायद यह मान लिया है कि गाँव के लोग गर्मी में तपकर आत्मनिर्भर बन जाएंगे। विभाग की तत्परता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी लोग सिर्फ तारों में करंट नहीं, जिम्मेदारों में हरकत आने का इंतजार कर रहे हैं।

ग्रामीणों ने कसा तंज

ग्रामीणों ने तंज कसते हुए कहा कि यदि इतनी ही तेजी से विभाग काम करता रहा तो आने वाले समय में मौसम विभाग को 'तेज हवा' की चेतावनी नहीं, बल्कि 'बिजली गायब होने' की चेतावनी जारी करनी पड़ेगी। लोगों का यह भी कहना है कि बिल जमा करने में एक दिन की देरी हो जाए तो विभाग की सक्रियता बिजली की स्पीड से भी तेज हो जाती है, लेकिन जब पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूबा हो तब जिम्मेदारों की ऊर्जा भी शायद बिजली के साथ ही चली जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर नवागांव फीडर की बिजली पहले आएगी या विभाग की नींद टूटेगी। फिलहाल खन्नौधी क्षेत्र की जनता अंधेरे में बैठकर यही सोच रही है कि अगली बार हवा चले तो पेड़ झुकें या पूरा बिजली विभाग!

स्टेट बैंक में पेंशनर्स की बैठक आयोजित

- पेंशनर्स के लिए अलग काउंटर खोलने की मांग

नवभारत,शहडोल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा शहडोल द्वारा शनिवार को बैंक सभागार में पेंशनर्स बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव गुप्ता की अगुवाई में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पेंशनर्स शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्य प्रबंधक रवीस एवं उप प्रबंधक सुशांत आचार्य ने बैंक द्वारा खाताधारकों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी। साथ ही साइबर ठगी से बचाव के उपायों एवं डिजिटल बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी विस्तारपूर्वक साझा की गईं।

इस अवसर पर प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन ऑफमध्यप्रदेश, संभाग शहडोल के महासचिव महेश प्रसाद द्विवेदी ने पेंशनर्स की सुविधा के लिए बैंक में अलग काउंटर खोले जाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव का उपस्थित पेंशनर्स ने करतल ध्वनि से समर्थन किया।बैठक में शासकीय सेवा निवृत्त पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. परमानंद तिवारी, प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के संभागीय महासचिव एवं पूर्व जिला योग प्रभारी महेश प्रसाद द्विवेदी, पूर्व प्राचार्य अरुण नामदेव, पूर्व जनसंपर्क अधिकारी शैलेन्द्र जार्ज, पूर्व प्रधानाचार्य जवाहर सिंह परिहार, सेवा निवृत्त शिक्षक एवं सह संभागीय संगठन मंत्री मध्यप्रदेश शिक्षक संघ विष्णु दास मिश्र, सेवा निवृत्त शिक्षक डी.पी. द्विवेदी सहित अन्य कई पेंशनर्स उपस्थित रहे।

कोयलांचल में खुलेआम चल रहा अवैध रेत व कोयले का कारोबार

नवभारत धनपुरी। कोयलांचल क्षेत्र धनपुरी,बुढार,अमलाई क्षेत्र में अवैध खनिज उत्खनन व परिवहन का कार्य खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे संचालित किया जा रहा है जिससे साफ पता चलता है इन अवैध खनिज व उत्खनन कर को संचालित करने वाले माफियाओं को प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ नहीं है सवाल यह भी उठता है समय-समय पर संबंधित विभाग द्वारा अवैध खनिज व परिवहन पर कार्यवाही भी की जाती है लेकिन बावजूद भी उसके माफियाओं का काला साम्राज्य रुकने का नाम नहीं लेता क्या स्थानीय प्रशासन द्वारा की जाने वाली समय-समय पर ऐसी कार्यवाही महज खानापूर्ति बनकर ही रह जाती है ।

बिना रेत टेंडर के बावजूद धड़ल्ले से निकल रही है गाड़ियां* कोयलांचल क्षेत्र के अंतर्गत अवैध रेट का उत्खनन व परिवहन खुलेआम किया जा रहा है ट्रैक्टर व टालियो के माध्यम से खुलेआम रेत का परिवहन क्षेत्र में वह जिले के बाहर भेजा जा रहा है आखिर इस पूरे मामले में स्थानीय प्रशासन क्या बेखबर है या फिर माफियाओं को उनकी मौन स्वीकृति मिली हुई है । प्रशासन पर भारी माफियाओं का साम्राज्य अगर स्थानीय प्रशासन व खनिज विभाग अवैध उत्खनन व परिवहन पर कार्यवाही के लिए घटनास्थल पर पहुंच भी जाता है तो माफियाओं व इनमें लिफ्त उनके गुर्गो द्वारा अधिकारियों पर जानलेवा हमला करने से भी परहेज नहीं करते जिले में कई विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी है जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी को अपनी शहादत देनी पड़ चुकी है इस संबंध में जब नवभारत प्रतिनिधि द्वारा जिला खनिज अधिकारी से चर्चा की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि हमारे पास जिले में 24 लोगों का स्टाफ है जिसमें 6 इंस्पेक्टर होने चाहिए लेकिन हमारे पास मात्र एक इंस्पेक्टर ही कार्यालय में पदस्थ हैं पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण हमें भी अवैध खनिज कार्यों में लिफ्ट लोगों को लिफ्त लोगों पर पर कार्यवाही करने में असुविधा होती है जिला खनिज अधिकारी राहुल संडिल्य शहडोल।

कार्यवाही की मांग | रोक लगाने वनमण्डला अधिकारी ने लिखा पत्र

जंगल की जमीन में बस स्टैंड और सभागार का निर्माण

नवभारत, ब्योहारी। आराजी खसरा न. 172 ब्योहारी के सम्पूर्ण खसरे मे राजस्व जंगल दर्ज है इसके बाद भी नगर परिषद द्वारा उसमे बस स्टैंड और अडोटोरियम (सभागार) का निर्माण कराया जा रहा है उक्त बात की शिकायत वार्ड क्रममांक 09 पार्षद धर्मेंद्र सिंह ने वनमण्डला अधिकारी उत्तर वन मण्डल शहडोल से कर निर्माण मे रोक लगाने और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग की थी जिसे वनमण्डलाधिकारी द्वारा गंभीरता से लेते हुए पत्र क्रमांक 3174 शहडोल दिनांक 06.05.26 को उप वनमण्डलाधिकरी ब्योहारी को भेज जांच कर वस्तु स्थित की जानकारी तत्काल चाही गयी साथ ही उक्त भूमि वन के रूप मे परिभाषित होने के कारण कार्य को तत्काल बंद कराने का आदेश दिया है।

लुटती रही जंगल की आबरू सोते रहे अधिकारी

आश्चर्य की बात है कि जंहा बस स्टैंड और अडोटोरियम का निर्माण नगर परिषद द्वारा कराया जा रहा है उसके चंद कदमो की दूरी पर एसडीओ और रेंजर जैसे जिम्मेदार अधिकारियो का निवास है। यंहा से आना जाना लगा रहता है इसके बाद भी किसी ने काम बंद कराने की हिम्मत नही दिखाई।शिकायतकर्ता का आरोप है कि क्या निर्माण जंगल की जमीन मे हो रहा है इसकी जानकारी नही थी या फिर कुछ और बात है जिसके कारण चुप्पी साध रखे थे।

नाले का बदला स्वरूप

नगर परिषद के ठेकेदार ने बस स्टैंड का निर्माण कराने के लिये वहाँ स्थिति नाले को पाट कर उसके स्वरूप में परिवर्तन किया गया किन्तु यंहा के जिम्मेदार अधिकारियो ने मुंह में ताला लगा लिया और चुपचाप तमासा देखते रहे इसकी जांच होनी चाहिये और ले आउट देने वाले दोषी उपयंत्री सहित सीएमओ के खिलाफकार्यवाही करने की मांग की जा रही है बरहाल देखना यह है कि उप वनमण्डला अधिकारी ब्योहारी इसे कितनी गंभीरता से लेते है और क्या कार्यवाही करते है।

नहीं उठा फोन -वनमण्डलाधिकारी शहडोल द्वारा जारी पत्र में एसडीओ उप वनमण्डलाधिकारी ब्योहारी ने अभी तक क्या कार्यवाही की है जानकारी लेने के लिये उनके शासकीय मोबाईल नम्बर पर कई बार सम्पर्क करना चाहा किन्तु उनके द्वारा फोन रिसीव नही किया गया।

निर्माण की आड़ में ठेकेदार ने बेची मुरुम

चर्चा है कि अडोटोरियम (सभागार) का निर्माण कराने के लिये ठेकेदार ने किसी स्थानीय ठेकेदार को पेटी मे काम दिया है जिसके द्वारा निर्माण के नाम पर वंहा जमीन समतल करने हेतु भारी भरकम मुरुम निकाल कर बेंचा गया है जबकि नियमानुसार उसे वंहा एकत्रित करना था इसके बाद उसकी नीलामी होनी चाहिए किन्तु ऐसा नहीं हुआ है। ठेकेदार द्वारा किसके कहने पर और किसे कितने मे बेंचा गया इसकी जांच कराकर कार्यवाही और राजस्व को हुए क्षति कि वसूली की मांग लोगों ने की है।